



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 1—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ११
No ११

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी ७, १९८४/पौष १७, १९०५
NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 7, 1984 PAUSA 17, 1905

एक भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नीयहन और परिग्रहन मंत्रालय
मंकलग

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 1984

सं० पी० डब्ल्यू०/पी० ई० ओ०-47/82 :- प्राक्कलन समिति सातवीं लोकसभा (इसकी 92वीं रिपोर्ट में विहित भिन्नाग्रिण सं०-92) ने यह भिन्नाग्रिण की है कि महासन्तनों के प्रशासन की अधिक कुशल धार पर प्रणितामयक बताने के उद्देश्य से प्रशासनिक प्रवृत्ति और प्रविष्टा का व्यापक समीक्षा करने के लिए एक प्रशासनिक मध्याम समिति नियुक्ति की जाय। भारत सरकार ने इस विस्तारिक के अनुपालन में महासन्तन मध्याम समिति गठित करके उस दिनांक किया है। इस समिति को संरचना निम्न प्रकार होगी :-

अथवा
मन्त्रः
श्री हा० शा० गेडे
श्री सा० सागराजीरावराव
श्री कृष्ण आर० शिंदे
श्री हनुमन्त भगवत्
श्री वी० क० शिंदे, नीयतुत, पद्मार्चिका
श्री क० ग० उमराव, अध्यापक, जम्बई पोर्ट ट्रस्ट
श्री टी० सी० दास, अध्यापक, कनकाता पोर्ट ट्रस्ट
श्री आर० परमेश्वर, अपर सचिव (प्रशास-
निक सुधार) गह मंत्रालय

वाइस एडमिरल एम० के० गय, पतंग आफ-
सर, कमांडिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमांड
श्री एस० एस० शुक्ला, वित्तीय सलाहकार
नौबहन और परिवहन मंत्रालय
श्री दिनेश कुमार जन, संयुक्त सचिव (पत्तन)
नौबहन और परिवहन मंत्रालय

सदस्य सचिव श्री एच० एन० कनिहारा, प्रबंध निदेशक
इंडियन पोर्ट्स एंजोसोसिएशन

2. समिति का कार्य क्षेत्र विस्तृत होगा --

(i) देश के मङ्गलानों के प्रभावत से सम्प्रति मातृद
कावुनी ढांचा, सरकार द्वारा मङ्गलानों को जाया किम गम
अनुदेश/मार्गदर्शिका, उत्कर्ष प्रभावितिक आग प्रचालन (वायों
हैडालेग सहित) पड्डी, मितिक प्रभावितिक आग प्रभावितिक प्रभावितिक
प्रभाव और कार्य विण्णालाग आग कन्वा; आग

(ii) (c) तकनीकी कार्रवाई और संवर्धित प्रकृत आग
कार्यकरण का प्राप्ति के लिए प्रोत्तिव कायूती, संगठनात्मक
और प्रशासनिक पतंगठन,

(ख) पत्तन क्षेत्र में जुटाई गई अतिरिक्त धनराशि का निवेश करने के लिए अपनाए जाने वाले विभिन्न पोषण की विधि और नीति,

(ग) संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग को सुनिश्चित करने की दृष्टि में जनशक्ति, उपकरण आदि का एक पत्तन से दूसरे पत्तन में हस्तांतरण,

(घ) कार्गो हैंडलिंग उपकरण और अन्य उपकरणों की आधुनिकीकरण,

(ङ) पत्तन प्रबालक और पत्तन की लागत और मूल्य निर्धारण को युक्तिमंगत बनाना,

(ज) पत्तन प्रबंध में व्यावसायिकता के प्रवर्तन और तकनीक में विशिष्टता का प्रोत्साहन देने के लिए अपेक्षित संस्थागत व्यवस्था और निवेश,

(झ) पत्तन क्षेत्र के विकास की कुल परिवहन पद्धति, और इसकी आधारभूत सुविधा वी अन्य अनुषंगी पद्धति.

3. समिति यदि यह आवश्यक समझे तो आमतौर पर यह देश के आर्थिक विकास तथा खासकर अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी लाने के लिए महापत्तनों की उत्प्रेरक की भूमिका निभाने के लिए अन्य सुझाव भी देगी।

4. समिति किसी ऐसे विशेष या व्यक्ति जिसके पास इस क्षेत्र में विशेष जानकारी है, उसे सहयोजित कर सकती है। आवश्यकतानुसार यह उपरोक्त क्षेत्र में से किसी भी क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए उप-दल गठित कर सकती है।

5. समिति की सहायतार्थ लिपिकवर्गीय कर्मचारी होंगे जिनकी नियुक्ति अलग से की जाएगी।

6. समिति अपनी रिपोर्ट एक वर्ष के भीतर पेश करेगी।

7. समिति अपनी अलग कार्य-पद्धति तैयार करेगी। यदि यह आवश्यक समझे तो कोई भी सूचना मांग सकती है और साक्ष्य ले सकती है। भारत सरकार के सभी महापत्तनों और मंत्रालय/विभाग तथा राज्य सरकारें इस समिति को आवश्यकतानुसार सूचना और सहायता प्रदान करेंगी।

8. अग्रासकीय सदस्यों की यात्रा में संबंधित यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ते का भुगतान भारत सरकार गौरवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। शासकीय सदस्यों में मन्व-धित खर्च उस संगठन द्वारा वहन किया जाएगा जिसमें वे कार्यरत हैं।

दिनेश कुमार शर्मा, सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT RESOLUTION

New Delhi, the 7th January, 1984

No. PW/PEO-47/82.-In pursuance of a recommendation made by Estimates Committee—Seventh Lok Sabha (Recommendation No. 92 contained in its 32nd Report) that administrative reforms committee be appointed to take up a comprehensive review of the administrative systems and procedure obtaining at major ports with the object of making their

administration more efficient and result-oriented, Government of India have decided to set up a Major Ports Reforms Committee consisting of the following :

Chairman	Shri D.D. Sathé
Members	Shri R. Balasubramanian Shri M.R. Shroff Shri Hiten Bhaya Shri B.K. Rao, Director General, (Shipping) Shri K.K. Uppal, Chairman, Bombay Port Trust. Shri T.C. Dutt, Chairman, Calcutta Port Trust. Shri R. Parumeswar, Additional Secretary (Administrative Reforms), Ministry of Home Affairs. Vice Admiral M.K. Roy, Flag Officer, Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command. Shri S.S. Shukla, Financial Adviser, Ministry of Shipping and Transport Shri D.K. Jain, Joint Secretary* (Ports), Ministry of Shipping and Transport.
Member Secretary	Shri H.N. Fotedar, Managing Director, Indian Ports Association.

2. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

(i) To examine the existing legal framework governing the administration of major ports in the country, instructions/guidelines issued by the Government to the major ports, their administrative and operational (including cargo handling) systems, labour productivity and motivation, financial management and performance; and

(ii) To make suitable recommendations regarding :

(a) the statutory, organisational and administrative restructuring required for securing integrated and coordinated development and functioning of the ports;

(b) the funding pattern and the policy to be followed for investment of any surpluses generated in the port sector;

(c) the inter-port transfer of manpower, equipment etc., with a view to ensuring optimal utilisation of resources;

(d) the modernisation of cargo handling equipment and other services;

(e) the rationalisation of port operations and port costing and pricing;

(f) the institutional arrangements and inputs required for promoting professionalism and encouraging specialisation of techniques in ports' management;

(g) the development of the port sector pari passu with the other sub-systems of the total transportation system and its infrastructure.

3. The Committee may make such other recommendations as it considers necessary to enable the major ports to fulfil their role as a catalyst for the country's economic development in general and international trade in particular.

4. The Committee may co-opt any expert or person having specialised knowledge of any subject connected with its deliberations. It may set up, if necessary, sub-groups for making a study in any of the aforesaid areas.

5. The Committee will be assisted by supporting secretarial staff to be appointed separately.

6. The Committee will submit its report within a period of one year.

7. The Committee will devise its own procedure. It may call for such information and take such evidence as it may con-

sider necessary. All Major Port Trusts and the Ministries/ Departments of the Government of India and State Governments will furnish such information and render such assistance as may be required by the Committee.

8. The expenditure on account of TA/DA etc. in connection with the journeys of the non-official members will be borne by the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport. The expenditure on this account in respect of official members will be borne by the respective organisations in which they are working.

D.K. JAIN, Jt. Secy.

